

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research

Department of Health Research, Ministry of Health

and Family Welfare, Government of India

No.16/56/2021-Admn.II

Dated: 19/08/2021

To

The Director/Directors-in-Charge of Permanent Institutes/Centers of ICMR

Subject:- Amendment to Public Procurement Policy for MSEs Order, 2012-reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer a copy of The Gazette of India, letter No.3002 dated 11.08.2021 received from O/o DC-MSME, Nirman Bhawan, New Delhi on the subject mentioned above for information and necessary action.

Yours faithfully

(Jagdish Rajesh)

Assistant Director General (Admn)

Encl: As above

Copy to :-

- (1) PS to DG/PS to Addl. DG/PS to Sr. DDG(A)/PS to Sr. FA
- (2) All Divisional Head
- (3) DDG(A)
- (4) ADG(A)
- (5) Dr. L.K.Sharma, Scientist "E" soft copy of the same has been mailed at your email ID (Sharma.lk@icmr.gov.in) for website upload.

Ansari Nagar, New Delhi - 110 029, India



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228903 CG-DL-E-11082021-228903

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3002]

No. 3002]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SHRAVANA 20, 1943

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3237(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करने का आदेश देती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्र नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म और लघु उद्यम (एम₋एस ई) संशोधन आदेश
 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के पैरा 3, उपपैरा (1) का लोप किया जाएगा।
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "7. सूक्ष्म <u>और लघु उद्यम विक्रेताओं</u> का विकास केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग य<u>ा पब्लिक सेक्टर के उ</u>पक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेंता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए और जी ई एम पोर्टल के माध्यम से उपापन के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम एस ई) के विकास पर फोकस करते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्य उपाय करेंगे।"
- उक्त आदेश में, पैरा 8 का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त आदेश के, उपाबंध के पैरा 2 के लिए निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :-

2 समिति की संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी, अथान :-

- (i) सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भंत्रालय अध्यक्ष
- (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रतिनिधि, नीति आयोग सदस्य ; (अपर सचिव श्रेणी से नीचे का न हों)
- (iii) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग सदस्य ;
- (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकार ई-मार्किट प्लेस सदस्य ; वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- (∀) सचिव का प्रतिनिधि, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय सदस्य ;
 (अपर सचिव श्रेणी से नीचे का न हो)
- (vi) सचिव का प्रतिनिधि
 सदस्य ;

 रक्षा मंत्रालय
 (अपर सचिव श्रेणी से नीचे का न हो)
- (vii) अध्यक्ष का प्रतिनिधि, रेलवे बोर्ड सदस्य ; रेल मंत्रालय (अपर सचिव श्रेणी से नीचे का न हो)
- (viii) अपर सचिव और विकास आयुक्त सदस्य सचिव (एमएसएमई)

[फा. सं. 12(4)/2020-एमए]

डी.के. सिंह, अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 581(अ), तारीख 23 मार्च, 2012 में और पश्चातवर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 5670(अ), तारीख 9 नवंबर, 2018 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

- S.O. 3237(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Amendment Order, 2021.
 - (2) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, (hereinafter referred to as the said order), in paragraph 3, sub-paragraph (1) shall be omitted.
- 3. In the said order, paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely:-
 - "7. Developing Micro and Small Enterprises vendors.- The Central Ministries or Departments or Public Sector-Undertakings shall take necessary steps to develop appropriate vendors by organising Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets focused on developing Micro and Small Enterprises (MSEs) for procurement through GeM Portal."

- 4. In the said order, paragraph 8 shall be omitted.
- 5. In the said order, for paragraph 2 of the Annexure, the following paragraph shall be substituted.
 - "2. The composition of the Committee shall be as follows, namely:-
 - (i) Secretary, Ministry of MSME

Chairman

(ii) representative of Chief Executive Officer, Niti Aayog (Not below the rank of Additional Secretary)

Member;

(iii) Secretary, Department of Public Enterprises

Member:

(iv) Chief Executive Officer, Government e-Marketplace
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry

: Member:

(v) representative of Secretary,
Department of Expenditure,
Ministry of Finance
(Not below the rank of Additional Secretary)

Member;

(vi) representative of Secretary, Ministry of Defence

Member:

_(Not below the rank of Additional Secretary)
(vii) representative of Chairman

Member;

Railway Board,

Ministry of Railways

(Not below the rank of Additional Secretary)

(viii) Additional Secretary and Development Commissioner (MSME)

: Member Secretary

[F. No. 12(4)/2020-MA]

D. K. SINGH, Addl. Secy. and Development Commissioner (MSME)

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 581(E), dated the 23rd March, 2012 and subsequently amended vide number S.O. 5670(E), dated the 9th November, 2018.